PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Haribhumi, Delhi
Friday 27th November 2015, Page: 6
Width: 10.12 cms, Height: 14.27 cms, a4, Ref: pmin.2015-11-27.53.91

जन औषधि योजना को लेकर आश्वस्त नहीं केंद्र सरकार!

अजीत पाठक . नई दिल्ली

केंद्र सरकार जन औषधि योजना की सफलता को लेकर मुतमईन नहीं हो पा रही, यही कारण है कि बड़े पैमाने पर इस योजना को लागू करने की रणनीति में बदलाव करना पड़ गया है। अब कुछ ही राज्यों में गिनती भर के स्टोर खोल उसकी सफलता के आंकलन के बाद ही सरकार इस योजना को बड़े पैमाने पर देश भर में लागू करने का मन बना रही है। पहले इस योजना के तहत देश भर में एक साथ तीन हजार जन औषधि स्टोर खोलने का लक्ष्य तय किया गया था। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, अब राजस्थान, केरल, पंजाब, दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में लगभग 200 स्टोर खोलने के बाद जो फीडबैक मिलेगा उसके बाद बड़े पैमाने पर इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। जबकि पहले इस योजना के तहत 18 राज्यों में एक साथ तीन हजार जन औषधि स्टोर खोलने की योजना थी। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से स्टोर खोलने के लिए जगह भी उपलब्ध कराने को कहा था। छग, मप्र, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 18 राज्यों ने मंत्रालय को स्टोर खोलने की अनुमति के साथ ही जगह उपलब्ध कराने पर हामी भर दी थी। 1मंत्रालय ने ये दावा भी किया था कि अक्टूबर 2015 के आखिर तक यह योजना शुरु हो जाएगी।

■ परियोजनाओं की रफ्तार को देखते हुए निर्माण उपकरण उद्योग अप्रत्याशित रफ्तार से वृद्धि दर्ज करेगा

इसलिए बदली रणनीति

मंत्रालय ने इस योजना के तहत 504 जेनरिक दवाओं को चिन्हित किया है। इसके अलावा, 106 मेडिकल डिवॉइस भी जन औषधि योजना में शामिल किए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि, अब तक अधिकतर दवाएं तैयार नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने स्टोर खोलने के लिए आवेदन की मांग के बावजूद कमीशन का अनुपात देखकर कम ही आवेदन मिले हैं।

यूपीए शासन में हुई थी शुरुआत

पूर्व की यूपीए सरकार के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की गई थी। उस वक्त 178 जनऔषधि स्टोर खोले थे। किंतु, जल्द ही इनकी संख्या सिमटकर 78 रह गई। एनडीए सरकार ने इसको नए सिरे से शुरु करने का दम भरा, किंतु उसका भी जोश ठंडा पड़ता दिख रहा।

Central Govt not confident about Jan Ausadhi Scheme
Jan Ausadhi.